बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 200 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 26 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो और बस से किया सफर, मेट्रो मंडे मुहिम को दिया बढ़ावा

नई दिल्ली। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक बार फिर मेट्रो और बस में सफर किया। उन्होंने अपने आवास से पैदल निकलकर सचिवालय जाने के लिए मेट्रो और इंटरसेप्टर बस का इस्तेमाल किया। यह पहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील से प्रेरित होकर शुरू की गई नई मेट्रो मंडे मुहिम का हिस्सा है। इससे पहले, पिछले सोमवार को भी उन्होंने ऐसा किया था। मेरा भारत, मेरा योगदान अभियान के तहत शुरू की गई इस पहल में मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने रोजाना के सफर के लिए सरकारी गाड़ियों के बजाय मेट्रो और बसों का इस्तेमाल किया।

सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम पर मचा बवाल, जयराम रमेश बोले- धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें

नई दिल्ली।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए, कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को सीबीएसई की कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में कथित अनियमितताओं के लिए सरकार से जवाबदेही की मांग की। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी से यह स्पष्ट करने को कहा कि शिक्षा मंत्री की अक्षमता को इतने लंबे समय तक क्यों जारी रहने दिया गया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (ओएसएम) लागू किया है, जिससे देशभर के लाखों बच्चों का शैक्षणिक भविष्य अधर में लटक गया है। पार्टी नेता के अनुसार, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत में 3 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम में अनियमितताओं के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर लिखा कि कक्षा 12 के उत्तीर्ण प्रतिशत में अभूतपूर्व 3 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है (88फीसदी से 85फीसदी) और यह प्रक्रिया अनियमितताओं से ग्रस्त रही है - धुंधली और अपठनीय उत्तर पुस्तिकाएं, गलत अंकन, छात्रों को गलत उत्तर पुस्तिकाओं का श्रेय देना, भुगतान में देरी और छात्रों से मनमाने ढंग से पुनर्मूल्यांकन शुल्क की मांग। उन्होंने सरकार पर नई प्रणाली लागू करने के लिए कथित तौर पर तैयार न होने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस बात की आलोचना की कि वे इन तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए आईआईटी कानपुर को लाकर खुद को मसीहा के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि इन समस्याओं का पहले से अनुमान क्यों नहीं लगाया गया? सीबीएसई और मंत्रालय ने इस ओएसएम प्रणाली को अपनाने से पहले सावधानीपूर्वक योजना क्यों नहीं बनाई? मंत्री जी को इस मुद्दे पर जवाब देने में इतना समय क्यों लगा?

कांग्रेस सांसद ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग दोहराई और प्रधानमंत्री से इस तरह की अक्षमता को जारी रहने देने पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि मंत्री प्रधान को देश को अपना इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को हमें यह जवाब देना चाहिए कि इस मंत्री को, जो अपनी अक्षमता से खुलेआम भारत के छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, इतने लंबे समय तक पद पर क्यों बने रहने दिया गया है।

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे, कहा- यह मोदी सरकार की रोज़ाना की डकैती

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में फिर से वृद्धि होने के बाद सोमवार को आरोप लगाया कि यह मोदी सरकार द्वारा रोजाना की जाने वाली डकैती है और इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख ने सवाल किया कि आखिर इस डकैती का फायदा किसे हो रहा है? पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर वृद्धि की गयी। पेट्रोल की कीमत 2.61 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम 2.71 रुपये प्रति लीटर बढ़ाये गये हैं। पिछले दो सप्ताह से भी कम समय में यह चौथी बार है जब कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 2.61 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 102.12 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 99.51 रुपये प्रति लीटर थी। डीजल के दाम 2.71 रुपये बढ़ाकर 95.20 रुपये प्रति लीटर कर दिए गए हैं, जो पहले

92.49 रुपये प्रति लीटर थे। खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, ईंधन लूट का रोजाना होने वाला आक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है।10 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमत में 7.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में डीजल-7.53 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने आम लोगों की बचत को जलाने के लिए पेट्रोल छिड़का है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है, वर्ष 2004 से 2014 के बीच, संप्रग सरकार के दौरान, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 175.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मोदी सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें एक प्रतिशत भी नहीं बढ़ीं। इसके बावजूद मोदी सरकार. पेट्रोल की कीमतें 2014 में 71.41 प्रति लीटर से बढ़कर 2026 में 102.12 प्रति लीटर हो गईं, 43.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई। डीजल की कीमतें 56.71 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गईं यानी 67.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार पिछले 12 वर्षों में 43 लाख करोड़ रुपये लूट चुकी है। खरगे ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी के साथ आज एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी के शेयरों में क्रमश- 5.8 प्रतिशत, 4.44 प्रतिशत और 3.90 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जनता से ज्यादा मुनाफ़ा कमाना भाजपा का डीएनए है। उनका कहना है, ईंधन मूल्य वृद्धि घरेलू बजट पर एक और झटका है, और इसका अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसानों से लेकर एमएसएमई तक, समाज का हर वर्ग भाजपा की लूट का खामियाजा भुगत रहा है। उन्होंने सवाल किया कि इस रोजाना होने वाली डकैती से किसे लाभ हो रहा है?

नीट पेपर लीक पर एमसीडी में बवाल, आप पार्षदों ने लहराए कॉकरोच वाले पोस्टर; हंगामे के चलते बैठक पोस्टपोन

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक सोमवार को उस समय हंगामेदार हो गई, जब आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के चलके निगम की बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक के दौरान आप पार्षदों ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। पार्षदों का आरोप था कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। सदन में आप पार्षदों ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा जैसे संवेदनशील एग्जाम में धांधली बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विरोध के चलते सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी रही। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद हाल ही में सोशल मीडिया से सुर्खियों में आई कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में

भी पोस्टर लेकर पहुंचे। नीट-यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसके जरिए एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कोर्सों में दाखिला मिलता है। 3 मई 2026 की परीक्षा के दौरान पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इसे लेकर शिक्षा मंत्री समेत केंद्र की भाजपा सरकार का विरोध होने लगा। सीबीआई ने मामले में धरपकड़ शुरू और दिल्ली समेत कई राज्यों में छापामारी कर पेपर लीक करने वालों को पकड़ा गया।

सरकार गिर जाएगी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, गौरव भाटिया बोले- भस्मासुर राहुल गांधी अराजकता फैला रहे

नई दिल्ली। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन पर टूलकिट पॉलिटिक्स फैलाने और केंद्र सरकार की स्थिरता के बारे में गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। भाटिया ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। ये टिप्पणियां राहुल गांधी के उस बयान के बाद आईं, जो उन्होंने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान दिया था, जहां उन्होंने दावा किया था कि यदि मौजूदा आर्थिक स्थिति बनी रहती है, तो सरकार अगले साल तक नहीं टिक पाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के नाम से सामने आए हालिया राजनीतिक बयानों पर बोलते हुए भाटिया ने सरकार के गिरने के दावों को बार-बार दोहराई जाने वाली गलत सूचना बताया। उन्होंने कहा कि कल एक और 'विवाद' सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि यह सरकार, जो पूरी ताकत से देश की सेवा कर रही है, एक साल के भीतर गिर जाएगी। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि 'भस्मासुर राहुल गांधी' हमें नहीं पता था कि भस्मासुर योतिषी भी बन जाएंगे। भाटिया ने राहुल गांधी की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें विरोधाभासी और भ्रम पैदा करने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक बैठक में कुछ टिप्पणियां कीं और बाद में बाहर एक अलग बयान जारी किया, जिस पर चर्चा हो रही है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है।

दिल्ली-छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा आपसी सहयोग- सीएम विष्णु देव साय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की सौजन्य भेंट

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके राजकीय निवास पर सौजन्य भेंट की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई यह मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने, सुशासन, शहरी विकास और जनहित से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच देश के बदलते प्रशासनिक और विकास परिदृश्य पर सकारात्मक बातचीत हुई।

बैठक में मुख्य रूप से शहरी विकास, सार्वजनिक सुविधाओं के

आधुनिकीकरण और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाले विभिन्न जनहितैषी विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर असहमति जताई कि राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से ही संघीय ढांचे को और मजबूती दी जा सकती है।

सीएम साय ने साझा की छत्तीसगढ़ की विकास गाथा

मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राय में संचालित की जा रही प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं और ढांचागत विकास के कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरह छत्तीसगढ़ तकनीक और सुशासन के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है।

देश के विकास में राज्यों का आपसी सहयोग बेहद महत्वपूर्ण

दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राष्ट्र के समग्र विकास में राज्यों की सक्रिय भूमिका और उनका आपसी सहयोग सबसे बड़ी धुरी है। विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ ही दोनों नेताओं ने भविष्य में भी एक-दूसरे के राज्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक अनुभवों और मॉडल्स को साझा करने की इच्छा जताई। इस सौजन्य भेंट को दोनों राज्यों के नीतिगत और विकासपरक संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

भीषण गर्मी

पिछले कुछ समय से मौसम वैज्ञानिकों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस साल भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इस खबर से सबसे ज्यादा चिंता कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को है। ऐसी भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि इस साल भी गर्मी विकराल रूप ले लेगी जिससे सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। खरीफ की फसल पर तो इसका बुरा असर पड़ेगा ही, पर रबी की ऊपज पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अमरीका और ईरान युद्ध के चलते पहले ही ऊर्जा संसाधनों पर महंगाई का असर दिखने लगा है और यदि गर्मी ने भी अपना असर दिखाया तो हालत बेकाबू हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बढ़ती गर्मी के कारण गेहूं का उत्पादन काफी कम होगा। इसके साथ ही फल और सब्जियों के उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नतीजतन खाद्य पदार्थों के दामों में काफी बढ़ोतरी की संभावना है। कितना असर होगा ये आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा दरअसल गर्मी बढ़ने का एक प्रमुख कारण सर्दियों में होने वाली बारिश का लगातार कम होते जाना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिसंबर, जनवरी और फरवरी में औसत तापमान से एक या दो डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इतना सा तापमान बढ़ने से बारिश की मात्रा घट गई है। ये तो रही कृषि उपादनों की बात लेकिन अगर शहरी जीवन को देखें तो ये समस्या और भी बड़ा विकराल रूप धारण करने जा रही है। हमारा अनुभव है कि गर्मियों में जब ताल-तलैये सूख जाते हैं और नदियों में भी जल की आवक घट जाती है तो सिंचाई के अलावा सामान्य जन-जीवन में भी पानी का संकट गहरा जाता है। नगर पालिकाएं आवश्यकता के अनुरूप जल की आपूर्ति नहीं कर पाती। इसलिए निर्बल वर्ग की बस्तियों में अक्सर सार्वजनिक नलों पर संग्राम छिड़ते हुए देखे जाते हैं। नलों में पानी बहुत कम देर के लिए आता है। मध्यम वर्गीय परिवारों को भी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पानी एकत्र करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। राजनेताओं, अधिकारियों और संपन्न लोगों को इन विपरीत परिस्थितियों में भी जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि ये लोग आवश्यकता से कई गुना ज्यादा जल जमा कर लेते हैं। असली मार तो आम लोगों पर पड़ती है। भीषण गर्मी पड़ने के साथ लोग कूलर या एयर कंडीशनर की तरफ भागते हैं। इससे जल और विद्युत दोनों का संकट बढ़ जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में जल आपूर्ति की मात्रा घटने से विद्युत उत्पादन गिरने लगता है। जैसे-जैसे समाज पारंपरिक तरीकों को छोड़ कर बिजली से चलने वाले उपकरणों की तरफ बढ़ रहा है वैसे-वैसे वातावरण और भी गर्म होता जा रहा है। एयर कंडीशनरों से निकलने वाली गर्म हवा भी वातावरण को प्रदूषित करने और गर्मी बढ़ाने का काम कर रही है। 1974-76 के बीच मैं एक स्वयंसेवक के रूप में मुरादाबाद के निकट अमरपुरकाशी गांव में समाज सेवा की भावना से काफी समय तक रहा। इस दौरान हर मौसम में गांव के जीवन को जिया। मुझे याद है कि मई जून की तपती गर्मी और लू के बावजूद हम सब स्वयंसेवक दोपहर में खुले दालान में नीम के पेड़ की छाया में सोया करते थे। तब वो छाया ही काफी ठण्डी लगती थी। गर्म लू जब पसीना सुखाती थी तो शरीर में ठंडक महसूस होती थी। इसी तरह रात में छत पर पानी छिड़क कर सब सो जाते थे। रात के ग्यारह-बारह बजे तक तो गर्म हवा चलती थी, फिर धरती की तपिश खत्म होने के बाद ठण्डी हवा चलने लगती थी। सूर्योदय के समय की बयार तो इतनी स्फूर्तिदायक होती थी कि पूरा शरीर नई ऊर्जा से संचालित होता था। वहां न तो फ्रिज का ठण्डा पानी था, न कोई और इंतजाम। लेकिन हैंडपम्प का पानी या मिट्टी के घड़े का पानी शीतलता के साथ सौंधापन लिये शरीर के लिए भी गुणकारी होता था। जबकि आज आरओ के पानी ने हम सबको बीमार बना दिया है। क्योंकि आरओ की मशीन जल के सभी प्राकृतिक गुणों को नष्ट कर देती है। कुएं से एक डोल पानी खींच कर सिर पर उड़ेलते ही सारे बदन में फुरफुरी आ जाती थी। जिससे दिन भर के श्रमदान की सारी थकावट क्षणों में काफूर हो जाती थी। आजकल हर व्यक्ति, चाहे उसकी हैसियत हो या न हो शरीर को कृत्रिम तरीके से ठण्डा रखने के उपकरणों को खरीदने की चाहत रखता है। हम सब इसके शिकार बन चुके हैं और इसका खामियाजा मौसम के बदले मिजाज और बढ़ती गर्मी को झेल कर भुगत रहे हैं। इस आधुनिक दिनचर्या का बहुत बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। हर शहर में लगातार बढ़ते अस्पताल और दवा की दुकानें इस बात का प्रमाण हैं कि 'सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम, शस्यश्यामलाम' वाले देश के हम सब नागरिक बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। न तो हमें अपने भविष्य की चिंता है, न ही सरकारों को। समस्याएं दिन-प्रतिदिन सुलझने के बजाए उलझती जा रही हैं। दूसरी तरफ हर पर्यावरणविद् मानता है कि पारंपरिक जलाशयों को सुधार कर उनकी जल संचय क्षमता को बढ़ा कर और सघन वृक्षावली तैयार करके मौसम के मिजाज को कुछ हद तक बदला भी जा सकता है। प्रधान मंत्री मोदी का जल शक्ति अभियान और बरसों से चले आ रहे पौधारोपण के सरकारी अभियान अगर ईमानदारी से चलाए जाते तो देश के पर्यावरण की हालत आज इतनी दयनीय न होती। सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा जहां एक ओर तो पौधारोपण व तालाब खोदने को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं जमीनी स्तर पर कथनी और करनी में काफी अंतर है। मिसाल के तौर पर जालौन क्षेत्र में 400 छोटे बांध बनाए गए थे। इनमें से आधे से ज्यादा तबाह हो चुके हैं। ललितपुर जिले में जल संरक्षण के लिए तीन करोड़ रुपये से चल रहा काम निरर्थक हो चुका है। इसी इलाके में बादहा और रसिन बांध के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हुए लेकिन इसका भी नतीजा शून्य ही रहा। इसलिए यदि हम पारंपरिक तरीकों पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे संकट आते रहेंगे।

ग्रीन कार्ड को 'रेड कार्ड'

एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो टैरिफ मुद्दे पर भारत-अमेरिका संबंधों में आए तनाव को कम करने और खराब रिश्तों को फिर से मुस्तैद करने के लिए भारत आए हुए हैं। मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया है और भविष्य में दोनों देशों के मिलजुल कर काम करने का संकल्प लिया। मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ भी मुलाकात कर रक्षा, व्यापार, हिन्द प्रशांत और पश्चिम एशिया तनाव मुद्दे पर बातचीत की। यह बैठकें केवल द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि दो बड़ी शक्तियों के फिर से समीकरण बनाने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण समझी जा रही हैं। अमेरिकियों के बारे में मशहूर है कि वे खुद को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नागरिक मानते हैं और अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं। इसी बीच अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में जबरदस्त बदलाव किया है जिससे लाखों भारतीय प्रभावित होंगे। नई नीति के मुताबिक ग्रीन कार्ड की इच्छा रखने वाले ज्यादातर अप्रवासियों को अमेरिका छोड़कर अपने देश में स्थित अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में आवेदन करना होगा। अब स्थायी निवास यानि ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले अधिकतर प्रवासियों को अपने देश लौटकर वहीं से आवेदन करना होगा। पहले कई लोग अमेरिका में रहते हुए ही 'एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस' प्रक्रिया पूरी कर लेते थे। यूएससीआईएस के प्रवक्ता जैक काहलर ने कहा, 'अब से अमेरिका में अस्थायी रूप से रह रहा कोई भी विदेशी नागरिक जो ग्रीन कार्ड चाहता है, उसे सामान्य तौर पर अपने देश लौटकर आवेदन करना होगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के।' एजेंसी ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के भीतर रहकर स्टेटस एडजस्टमेंट अब एक अपवाद माना जाएगा और हर आवेदन की व्यक्तिगत स्तर पर सख्ती से जांच होगी। यूएससीआईएस ने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा कि छात्र, अस्थायी कर्मचारी और पर्यटक सीमित अवधि और विशेष उद्देश्य के लिए अमेरिका आते हैं। उनका अमेरिका आना ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का पहला कदम नहीं माना जाना चाहिए। नई नीति का सबसे ज्यादा असर भारतीय नागरिकों पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड आवेदकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। वित्त वर्ष 2026 में भारत के आवेदकों के लिए उपलब्ध सभी ईबी-2 वीजा का उपयोग हो चुका है। अब वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए भारतीय आवेदकों को कोई और ग्रीन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए उन डिग्री प्राप्त भारतीय पेशेवरों के लिए ग्रीन कार्ड के दरवाजे अब बंद हो गए हैं। अमेरिका में 12 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी स्थायी निवासी बनने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें वह छात्र भी शामिल है जो वहां अब नौकरियां कर रहे हैं। अमेरिका में पढ़ने गए भारतीय छात्रों और पहले से ही वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों का सपना होता है कि उन्हें किसी न किसी तरह से ग्रीन कार्ड मिल जाए लेकिन अब उनका सपना चूर-चूर हो गया है। हाल ही के वर्षों में अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी दाखिल हुए हैं और ग्रीन कार्ड सिस्टम का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। छात्र, अस्थाई कर्मचारी या टूरिस्ट वीजा पर आने वाले गैर प्रवासी थोड़े समय के लिए या किसी खास मकसद से अमेरिका आते हैं। ?सिस्टम यही कहता है कि जब उनका दौरा खत्म हो जाए तो वह वापिस चले जाएं लेकिन वे अवैध रूप से रहना शुरू कर देते हैं और? फिर वे ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया का ?हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। कई मामलों में देखा गया कि एच-1बी वीजा पर गए लोग किसी अमेरिकी युवती से शादी कर लेते हैं और ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं। अमेरिका में काम करने वाले अप्रवासी युवाओं के जीवन साथी विजटर वीजा पर अमेरिका आते हैं और फिर ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वालों के भी अनेक मामले सामने आए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीयों में विदेशों में रहकर अपना भविष्य स्वर्णिम बनाने की ललक बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रम्प का शुरू से ही अप्रवासियों के मामले में बहुत सख्त रुख रहा है। अवैध अप्रवासन को कम करना उनका चुनावी मुद्दा रहा है। ट्रम्प प्रशासन लगातार अप्रवासियों की संख्या कम करने की कोशिश कर रहा है। अनेक अवैध अप्रवासी भारतीयों को जंजीरों में जकड़ कर भारत भेजा जा चुका है। अब अमेरिका में मध्यावधि चुनाव आ रहे हैं। टैरिफ वॉर और पश्चिम एशिया संकट को लेकर ट्रम्प और उनकी पार्टी की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। उनकी पार्टी के भीतर और देश में युद्ध विरोधी भावनाएं जोर पकड़ रही हैं। इसीलिए ट्रम्प ईरान से सम्मानजनक समझौते के मार्ग तलाश रहे हैं। ट्रम्प प्रशासन ने इमिग्रेशन के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकियों को यह दिखाने की कोशिश की है कि वे अप्रवासियों को नहीं आने दे रहे और ऐसी प्रक्रिया बना रहे हैं जिससे लोगों का आना मुश्किल हो जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि अप्रवासी भारतीयों ने अमेरिका के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अमेरिका के सरकारी खजाने में अरबों डॉलर का योगदान देते हैं लेकिन नई नीति ने पेशेवरों और छात्रों को अनिश्चितता में डाल दिया है। नई नीति को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ का मानना है कि नई नीति अमेरिका को खुद चोट पहुंचाने वाली है। अप्रवासी भारतीयों का कहना है कि अमेरिकी सरकार को अपने इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। क्योंकि भारतीयों समेत दुनियाभर के हजारों लोगों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था और समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए अनुमति प्रदान करने वाला दस्तावेज है। यह दस्तावेज किसी भी व्यक्ति को अमेरिकी नागरिकों की तरह ही लाभ और अधिकार देता है। ग्रीन कार्ड धारक को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है लेकिन देश में कहीं भी भ्रमण करने से लेकर काम करने तक का बराबर अवसर मिलता है।

सम्पादकीय...

सामरिक और आर्थिक मायने

भारत और साइप्रस के बीच हाल में हुई रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न समझौतों के कई बड़े कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक मायने हैं। देखा जाए तो यह केवल द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार नहीं, बल्कि यूरोप, भूमध्यसागर, पश्चिम एशिया और वैश्विक शक्ति-संतुलन से भी जुड़ा कदम माना जा रहा है। चूंकि तुर्की और साइप्रस के बीच गहरी दुश्मनी है, इसलिए भारत उसे तुर्किये के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि तुर्किये भारत के चिर शत्रु पाकिस्तान का मित्र है। इस प्रकार भारत के रणनीतिकारों ने एक तीर से कई शिकार किये हैं। उल्लेखनीय है कि साइप्रस एक द्वीप है, इसलिए उसकी लैंड बॉर्डर तुर्की के साथ नहीं लगती है। लेकिन समुद्री मार्ग से साइप्रस और तुर्की के बीच की दूरी महज 65 से 70 किलोमीटर है। यही नहीं, साइप्रस तुर्की से 85 गुना छोटा देश है। इसलिए तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। चूंकि तुर्की तो साइप्रस को एक देश भी नहीं मानता। लिहाजा दोनों देशों के बीच टकराव हमेशा बना रहता है। गत दिनों उसी देश साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स दिल्ली के दौरे पर आए। इस दौरान भारत और साइप्रस के बीच 14 मुद्दों पर ऐतिहासिक डील फाइनल हो गई। आइए अब हम आपको इन 14 डील्स के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझिए आखिर में ये प्रमुख डील और समझौते क्या हैं? तो यह जान लीजिए कि भारत और साइप्रस ने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया है। जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग रोडमैप, आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्यसमूह, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार से जुड़े कई समझौते हुए हैं। पहला, यूरोप में भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत हुई है, क्योंकि साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है। ऐसे में भारत को यूरोप के भीतर एक भरोसेमंद सहयोगी मिल रहा है। साइप्रस ने भारत-ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का समर्थन भी किया है। इसका अर्थ है कि भारत की यूरोप तक आर्थिक पहुँच मजबूत होगी। इससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार के दरवाजे और खुल सकते हैं। वहीं भारत की कूटनीतिक आवाज ईयू मंचों पर अधिक प्रभावी हो सकती है। दूसरा, तुर्किये-पाकिस्तान समीकरण का संतुलन तोड़ने में अब भारत को मिलेगी सहूलियत, क्योंकि साइप्रस और तुर्किये के बीच लंबे समय से तनाव है। दूसरी ओर तुर्किये कई बार पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर मुद्दे पर बोलता रहा है। ऐसे में भारत-साइप्रस निकटता को एक भू-राजनीतिक संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन दोहराया, जबकि साइप्रस भारत के आतंकवाद विरोधी रुख के करीब दिखा। तीसरा, चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब भी माना जा रहा है, क्योंकि भारत, साइप्रस और यूरोप के बीच बढ़ती साझेदारी को चीन की Belt and Road रणनीति के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषकर समुद्री व्यापार, सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है। चौथा, आईएमईसी कॉरिडोर को मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा भारत की बड़ी रणनीतिक परियोजनाओं में से एक है। खास बात यह कि साइप्रस पूर्वी भूमध्यसागर में स्थित होने के कारण इस कॉरिडोर का महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और समुद्री केंद्र बन सकता है।

तो क्या खामोशी भी हो सकती है वायरल ?

वर्चुअल साहित्यिक बैठकों के मुख्य विषय अपने डिजिटल मंचों (जैसे यूट्यूब और फेसबुक) पर जो वीडियो सीरीज और चर्चाएं लाती हैं, उन्हें अमृता के प्रशंसकों द्वारा एक आधुनिक 'साहित्यिक बैठक' की तरह देखा जाता है। इन बैठकों के मुख्य पहलू हैं- 'विभाजन का दर्द और 'अज आखां वारिस शाह नूं।' वरदा अपनी बैठकों में भारत-पाकिस्तान विभाजन (1947) पर लिखी अमृता की सबसे प्रसिद्ध कविता 'अज आखां वारिस शाह नूं' को बेहद मार्मिक ढंग से बयां करती हैं। वह दोनों पंजाबों (चढ़दा और लहंदा पंजाब) के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करती हैं। साहिर, इमरोज और अमृता का त्रिकोण वरदा ने अमृता प्रीतम की आत्मकथा 'रसीदी टिकट' के अंशों को अपनी बैठकों का हिस्सा बनाया है। वे साहिर लुधियानवी के लिए अमृता के अनकहे प्यार और चित्रकार इमरोज के साथ उनके अनूठे सह-जीवन के अनछुए पहलुओं को दर्शकों के सामने रखती हैं।

प्रश्न किसी शब्द विशेष के नाम पर सोशल मीडिया किसी एक ऑपरेटर द्वारा एक नई पार्टी की स्थापना तक सीमित नहीं है। प्रश्न गंभीर है और व्यापक भी। वैसे किसी भी हंगामे या सनसनी की उम्र दो या चार दिन ही होती है। काश ऐसा मुमकिन हो जाए। यह नई पार्टी सोशल मीडिया पर जन्मी है और अमेरिका में बैठे एक 30 वर्षीय भारतीय ने अपने 'सोशल मीडिया पेज' पर ही इसका गठन घोषित किया है। इस दिशाहीन आक्रोश का आलम यह है कि अब सोशल मीडिया पर इसके 1.7 करोड़ 'फॉलोअर' हो गए हैं। यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। 30 वर्षीय इस युवा अभिजीत दिपके का संबंध महाराष्ट्र से है और परिवार छत्रपति संभाजी नगर में रहता है। वह एक पेशेवर राजनीतिक-संचार रणनीतिकार है। वर्ष 2022-23 में 'आम आदमी पार्टी' के आईटी प्रकोष्ठ से जुड़ा रहा है। अब इस अभियान के खिलाफ भी कुछ टैली-रणनीतिकार समानांतर 'रूप' से पेज बनाने व सोशल मीडिया पर सक्रिय होने में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर इस घात-प्रतिघात की रोकथाम का भी कोई उपाय नहीं, मगर चिंता इस बात की है कि इसी तर्ज पर विश्व में किसी भी देश का कोई रणनीतिकार कोई भी मुहिम छेड़कर देश के अधिकांश युवाओं का ध्यान भटका सकता है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा खतरा यही रहता है कि अपने-अपने प्रोफेशनल कैरियर में लगे युवा वैज्ञानिक युवा, सोशल युवा छात्र, युवा पत्रकार इसी 'मीडिया पेज' पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। इस सारे घटनाक्रम से यह भी पता चलता है कि अब इंस्टाग्राम व अन्य सोशल मीडिया चैनल, कभी-कभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हावी होने लगे हैं। यह समूचा घटनाक्रम देश के अग्रणी लोगों को भी चेता रहा है कि भविष्य में वे किसी भी विवादास्पद टिप्पणी से दूरी बनाए रखें। देश के सीजेआई एक सुसंस्कृत परिवार से हैं और निचली पायदान से अपनी बौद्धिक क्षमता व सतत परिश्रम से शिखर तक पहुंचे हैं। यदि वह ऐसी किसी टिप्पणी से परहेज रखते तो बेहतर रहता। न्यायिक-प्रणाली व न्यायिक सक्रियता के क्षेत्र में उनकी कुछ टिप्पणियों का व्यापक स्वागत भी हुआ है।

बेहतर होता कि वह अपने पद की गरिमा के अनुरूप ऐसी किसी भी टिप्पणी से परहेज करते, जो उनके कद व प्रतिष्ठा पर हल्की सी भी खरोंच डाल सके। अब यह प्रश्न भी बेमानी है कि इस 'सोशल मीडिया चैनल' के पीछे किसका हाथ है? हो सकता है कि यह एक सहज युवा-आक्रोश का मामला हो और यह भी संभव है कि किसी प्रतिपक्षी दल ने इसे अपनी रणनीति का माध्यम बनाया हो। ऐसे सिलसिले तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक सहज अंग बन चुके हैं। ये सिलसिले अतीत में कुछ साहित्यिक संस्थानों की कार्यप्रणाली को लेकर भी चले हैं। लेकिन ऐसे सिलसिले तो जारी रहेंगे और बेहतर है कि उनकी जद में आने से बचा जाए। हालांकि वर्षों पहले कवि दुष्यंत ने अपनी एक काव्य टिप्पणी में चेताया भी था- आप बचकर चल सकें, ऐसी कोई सूरत नहीं, मगर जब तक ये तूफान किसी अगले नए हंगामे के लिए रास्ता नहीं छोड़ता, तब तक यह सब सिलसिले तो चलते रहेंगे। प्रश्न यह भी है कि क्या ऐसे किसी अभियान का इतना व्यापक प्रयोग किसी सकारात्मकता के लिए चलेगा। युवाओं में 'स्टार्ट अप्स' के लिए बाजार जुटाने व उन्हें ठोस व्यावहारिक धरातल पर खड़ा करने में मदद व समुचा दिशा ज्ञान अभी भी बकाया है। इसी दिशा में पाकिस्तान की एक युवा अदीब वरदा शहजादी द्वारा सोशल मीडिया पर सक्रियता को भी प्रेरक आधार बनाया जा रहा है। अपने देश पाकिस्तान के जहरीले माहौल में भी वह सोशल मीडिया पर 'अमृता की बैठक' और 'पंजाबी गर्ल स्पीक्स' सरीखी साहित्यिक बैठकें व 'लिट फेस्ट' आयोजित करती है। शहजादी ने नई दिल्ली स्थित दक्षिण-एशियाई यूनियन से समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और बाद में लाहौर के जीसी विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। वह सोशल मीडिया पर 'लहंदा पंजाब' व 'चढ़दा पंजाब' के विषयों पर लगातार सक्रिय रहती है। यह अलग बात है कि वहां के 'लाहौर लिट फेस्टिवल' या 'कराची लिट फेस्ट' में उसे विशेष महत्व नहीं दिया जाता लेकिन गुजरांवाला की यह बेटी पाकिस्तान की एक बेहद लोकप्रिय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, कहानीकार और प्रस्तुतकर्ता है, से मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर 'द पंजाबी गर्ल' के नाम से जाना जाता है। वह अपनी भावुक प्रस्तुतियों के जरिए मशहूर पंजाबी कवयित्री अमृता प्रीतम की यादों, उनके जीवन और उनके अमर साहित्य को जीवित रखने का काम कर रही है। चूंकि अमृता प्रीतम का निधन साल 2005 में हो गया था, इसलिए वरदा शहजादी और अमृता प्रीतम के बीच सीधे तौर पर कोई मुलाकात या समकालीन 'साहित्यिक बैठक' संभव नहीं थी। इसके बावजूद, वरदा शहजादी ने अपने वीडियो, पॉडकास्ट और वर्चुअल साहित्यिक सत्रों के माध्यम से अमृता प्रीतम के साथ एक गहरा 'वैचारिक और रूहानी' संवाद स्थापित किया है। वर्चुअल साहित्यिक बैठकों के मुख्य विषय अपने डिजिटल मंचों (जैसे यूट्यूब और फेसबुक) पर जो वीडियो सीरीज और चर्चाएं लाती हैं, उन्हें अमृता के प्रशंसकों द्वारा एक आधुनिक 'साहित्यिक बैठक' की तरह देखा जाता है। इन बैठकों के मुख्य पहलू हैं- 'विभाजन का दर्द और 'अज आखां वारिस शाह नूं।' वरदा अपनी बैठकों में भारत-पाकिस्तान विभाजन (1947) पर लिखी अमृता की सबसे प्रसिद्ध कविता 'अज आखां वारिस शाह नूं' को बेहद मार्मिक ढंग से बयां करती है। वह दोनों पंजाबों (चढ़दा और लहंदा पंजाब) के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करती है। साहिर, इमरोज और अमृता का त्रिकोण वरदा ने अमृता प्रीतम की आत्मकथा 'रसीदी टिकट' के अंशों को अपनी बैठकों का हिस्सा बनाया है। वे साहिर लुधियानवी के लिए अमृता के अनकहे प्यार और चित्रकार इमरोज के साथ उनके अनूठे सह-जीवन के अनछुए पहलुओं को दर्शकों के सामने रखती है।

क्यों ग्रामीण विकास तय करेगा 2047 तक विकसित भारत की यात्रा

1 जुलाई 2026 से भारत के ग्रामीण विकास ढांचे में एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वीबी-जी राम जी लागू होने जा रहा है। यह केवल किसी पुरानी योजना की जगह नई योजना लाने का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की विकास प्राथमिकताओं में बड़े बदलाव का संकेत भी है। अब ध्यान केवल अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराने पर नहीं रहेगा, बल्कि गांवों की दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता को मजबूत करने पर भी केंद्रित होगा। करीब दो दशकों तक मनरेगा ने ग्रामीण आजीविका को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से आर्थिक संकट के समय। लाखों परिवारों को रोजगार और आय का सुरक्षा कवच मिला। लेकिन आज ग्रामीण भारत तेजी से बदल रहा है। लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं।

गांव पहले की तुलना में अधिक जुड़े हुए हैं और विकास को लेकर लोगों की अपेक्षाएं भी बदल चुकी हैं। अब ग्रामीण समुदाय केवल मजदूरी आधारित सहायता नहीं, बल्कि बेहतर बुनियादी ढांचा, मजबूत कृषि व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर और स्थायी आय के साधन चाहते हैं। नई व्यवस्था इन्हीं बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आजीविका सुरक्षा को परिसंपत्ति निर्माण, स्थानीय योजना निर्माण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से जोड़ा गया है। कई मायनों में यह 'विकसित भारत' के उस बड़े लक्ष्य को दर्शाता है, जिसमें विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे।

2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा

महात्मा गांधी का मानना था कि भारत का भविष्य उसके गांवों की ताकत से तय होगा। उनका 'ग्राम स्वराज' का विचार आत्मनिर्भरता, स्थानीय भागीदारी और सशक्त ग्रामीण समुदायों पर आधारित था। आज भी यह विचार उतना ही प्रासंगिक है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा केवल शहरों की प्रगति से पूरी नहीं होगी, बल्कि ग्रामीण भारत के व्यापक परिवर्तन पर भी निर्भर करेगी। मजबूत गांव, उत्पादक कृषि व्यवस्था और सशक्त पंचायतें इस प्रक्रिया के केंद्र में रहेंगी। नई व्यवस्था में 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' पर दिया गया विशेष जोर इसी कारण महत्वपूर्ण है। सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप सरकार ने राज्यों की अधिक सक्रिय भागीदारी की भी परिकल्पना की है, ताकि पंचायत स्तर पर परियोजनाओं को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने में राज्यों की भूमिका और मजबूत हो सके। नई व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए वार्षिक रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यह उन परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकता है, जो अकुशल श्रम के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। इस योजना के पीछे सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता भी उल्लेखनीय है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना हेतु 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि राज्यों के योगदान को जोड़ने पर कुल व्यय 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। इतना बड़ा निवेश ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति दे सकता है।

> ग्रामीण उत्पादकता में वृद्धि, मजबूत बुनियादी ढांचा और स्थानीय उद्यमों का विकास भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वीबी-जी राम-जी की व्यापक सोच इसी दृष्टिकोण में निहित है। यह गांवों को राष्ट्रीय विकास और आर्थिक प्रगति का सक्रिय भागीदार मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि विकसित भारत का मार्ग सशक्त गांवों, आत्मनिर्भर समुदायों और समावेशी विकास से होकर गुजरता है। इसलिए विकसित भारत की राह भारत के गांवों, खेतों, पंचायतों और ग्रामीण उद्यमों से होकर ही निकलेगी। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह नई व्यवस्था महात्मा गांधी के गांवों की ताकत पर आधारित विचार और प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प - दोनों को आगे बढ़ाने का प्रयास है।

नई व्यवस्था के तहत सबसे बड़ा बदलाव टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर देना है। रोजगार सृजन को अब ऐसे कार्यों से जोड़ा जा रहा है, जो लंबे समय तक गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। योजना में जल संरक्षण, सिंचाई सहायता, ग्रामीण संपर्क मार्ग, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और जलवायु अनुकूल विकास जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। यहीं पर यह नई व्यवस्था महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। जब सार्वजनिक निवेश के माध्यम से ऐसी परिसंपत्तियां तैयार होती हैं, जो निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी स्थानीय आजीविका को लंबे समय तक सहारा देती रहें, तब विकास का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचता है। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू जलवायु अनुकूल विकास पर दिया गया विशेष जोर है। आज ग्रामीण भारत अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और अत्यधिक मौसमीय घटनाओं जैसी बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसका सीधा असर कृषि और ग्रामीण आय पर पड़ता है। भारत अब जलवायु अनुकूलन को ग्रामीण विकास से अलग करके नहीं देख सकता। जल सुरक्षा, वाटरशेड प्रबंधन और जलवायु के अनुरूप बुनियादी ढांचे का निर्माण गांवों के लिए आर्थिक प्राथमिकता बनता जा रहा है। यह योजना बाढ़ से बचाव के लिए तटबंधों को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी सुनिश्चित करेगी।

योजना के क्रियान्वयन में तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, जियो-टैगिंग और डिजिटल ट्रैकिंग जैसे उपायों से गड़बड़ियों को कम करने और निगरानी को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही समय पर मजदूरी भुगतान और शिकायत निवारण प्रणाली को भी अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। पिछले वर्षों में भुगतान में देरी ग्रामीण रोजगार योजनाओं के प्रति लोगों के विश्वास को कमजोर करती रही है। तेज भुगतान व्यवस्था और बेहतर निगरानी प्रणाली से जमीनी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में सुधार आ सकता है। आने वाले दो दशकों में भारत की विकास गाथा केवल शहरों के विस्तार से तय नहीं होगी, बल्कि गांवों के उत्थान से भी निर्धारित होगी।

ग्रामीण उत्पादकता में वृद्धि, मजबूत बुनियादी ढांचा और स्थानीय उद्यमों का विकास भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वीबी-जी राम-जी की व्यापक सोच इसी दृष्टिकोण में निहित है। यह गांवों को राष्ट्रीय विकास और आर्थिक प्रगति का सक्रिय भागीदार मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि विकसित भारत का मार्ग सशक्त गांवों, आत्मनिर्भर समुदायों और समावेशी विकास से होकर गुजरता है। इसलिए विकसित भारत की राह भारत के गांवों, खेतों, पंचायतों और ग्रामीण उद्यमों से होकर ही निकलेगी। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह नई व्यवस्था महात्मा गांधी के गांवों की ताकत पर आधारित विचार और प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प -दोनों को आगे बढ़ाने का प्रयास है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने करन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैण्डवनगर एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/36882)

जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर दिए सख्त निर्देश

कुशीनगर।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग की विभिन्न समितियों की संयुक्त समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला स्वास्थ्य समिति, रोगी कल्याण समिति, जिला क्षय रोग समिति, संचारी रोग नियंत्रण समिति, जिला एड्स समन्वय समिति, फाइलेरिया उन्मूलन समिति तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रेरणा कैंटीन के संचालन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि आठ स्थानों पर कार्यवाही चल रही है, जबकि अन्य स्थानों पर प्रक्रिया जारी है। आशा कार्यकर्त्रियों सहित लंबित भुगतानों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी भुगतान तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भुगतान में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही निष्क्रिय एवं कार्य में रुचि न लेने वाली आशाओं के विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, अस्पतालों में साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति एवं मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा के दौरान नियमित साफ-सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव एवं जनजागरूकता अभियान प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए गए। वहीं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए टीबी मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग एवं समय से उपचार सुनिश्चित करने को कहा गया। जिला एड्स समन्वय समिति की समीक्षा में एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर संचालित करने तथा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत शत-प्रतिशत दवा सेवन सुनिश्चित कराने पर बल दिया गया। आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने लंबित सर्वे कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। संदेहास्पद आंकड़े प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने संबंधित बाबू एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को नोटिस जारी करने तथा डिप्टी सीएमओ को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, टीकाकरण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा आयुष विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनपद की चार चीनी मिलों ने किया शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान

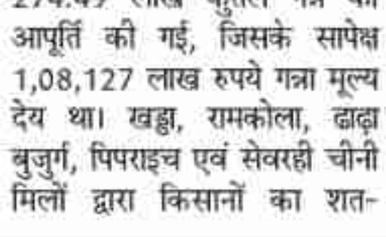

विभाग।

जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकी ने बताया कि पेराई सत्र 2025-26 में जनपद कुशीनगर में 96,603 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती की गई। जनपद की 14 गन्ना समितियों से जुड़े 2,14,815 किसानों द्वारा खड्डा, रामकोला (पी.), ढाढ़ा बुजुर्ग (हाटा), सेवरही, पिपराइच (गोरखपुर) एवं गड़ौरा (महराजगंज) चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति की गई। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा कुल 274.49 लाख कुंतल गन्ने की आपूर्ति की गई, जिसके सापेक्ष 1,08,127 लाख रुपये गन्ना मूल्य देय था। खड्डा, रामकोला, ढाढ़ा बुजुर्ग, पिपराइच एवं सेवरही चीनी मिलों द्वारा किसानों का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी के अनुसार अब तक कुल 1,07,921.95 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। केवल गड़ौरा चीनी मिल, महराजगंज पर 205.05 लाख रुपये गन्ना मूल्य अवशेष है। उक्त मिल द्वारा 1,935.84 लाख रुपये देय राशि के सापेक्ष 1,730.79 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अवशेष भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय की ओर से संबंधित चीनी मिल को नोटिस जारी किया गया है। जिला गन्ना अधिकारी ने कहा कि किसानों के हितों की सुरक्षा एवं समयबद्ध गन्ना मूल्य भुगतान शासन एवं प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा शेष भुगतान भी शीघ्र कराए जाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

गड़ौरा चीनी मिल पर 205.05 लाख रुपये बकाया

विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

पडरौना, कुशीनगर।

विशुनपुरा विकास खंड के खेसिया गांव में सोमवार को बाल-अनुकूल, मानसिक एवं बौद्धिक दिव्यांगता, दहेज प्रथा उन्मूलन, महिला कल्याण तथा हीट वेव एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्रमिक सुविधा केंद्र एक्शनएड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार त्यागी के मार्गदर्शन तथा सचिव भुवन (जज सीनियर डिवीजन) के नेतृत्व में आयोजित किया गया। शिविर में मानसिक रूप से बीमार एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, दहेज प्रथा उन्मूलन और श्रमिकों पर हीट वेव एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई।

विधिक जानकारी देते हुए रामवृक्ष गिरि ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार या दिव्यांग व्यक्तियों को भी सामान्य नागरिकों के समान सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने दहेज प्रथा को सामाजिक बुराई बताते हुए इसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। हीट वेव एवं जलवायु परिवर्तन का असंगठित श्रमिकों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हुए दिनेश प्रसाद ने श्रमिकों को बचाव के उपाय बताए। इस दौरान श्रमिकों ने भी अपनी समस्याएं साझा कीं। महिला कल्याण विभाग से आए नलिन सिंह ने महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में एक निराश्रित महिला एवं दो बच्चों की पहचान मुख्यमंत्री बाल कल्याण सामान्य योजना के लिए की गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजीव कुमार ने आवश्यक दस्तावेज एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी बुद्धरतन एवं धर्मशीला ने विभिन्न स्तरों पर गठित बाल कल्याण समितियों एवं विधिक सेवाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मोतीलाल, हरि, सुरेंद्र, गुलाइची देवी, पुरनी देवी, संतरा, रूना, चंदा देवी सहित बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे।

देवरिया बाईपास की धीमी प्रगति पर भड़के डीएम, जून तक हर हाल में सड़कें सुधारने का अल्टीमेटम

जिलाधिकारी बोले– बरसात से पहले जनसुविधा के प्रोजेक्ट्स में शिथिलता बर्दाश्त नहीं

देवरिया।

जनपद की जीवनरेखा मानी जाने वाली प्रमुख सड़क परियोजनाओं की कछुआ गति और कार्यदायी संस्थाओं की हीलाहवाली पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई और भूमि अधिग्रहण से जुड़े अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मानसून की दस्तक से पहले यानी जून माह तक सभी प्रमुख सड़कों के निर्माण में अपेक्षित प्रगति दिखनी चाहिए। विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में सबसे यादा गाज 613 करोड़ की लागत वाली देवरिया बाईपास सड़क परियोजना पर गिरी। एक अगस्त 2025 से शुरू हुई इस बेहद महत्वपूर्ण परियोजना की जमीनी प्रगति उम्मीद से काफी कम मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए कि वे कार्यबल बढ़ाकर निर्माण में तेजी लाएं, ताकि जुलाई 2027 की निर्धारित समय-सीमा से पहले जनता को इसका लाभ मिल सके। इसी तरह 13 करोड़ की ही लागत से बन रहे 44.995 किलोमीटर लंबे नवलपुर-सिकंदरपुर मार्ग की समीक्षा में पाया गया कि देवरिया के हिस्से वाले 16 किलोमीटर के भाग में अब तक महज 30 प्रतिशत ही भौतिक प्रगति हुई है, जिस पर डीएम ने गति बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के वित्तीय और भौतिक आंकड़े भी खंगाले गए। 598 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन राम-जानकी मार्ग की प्रगति 53.60 प्रतिशत पाई गई, जिसे मई 2027 तक पूरा होना है। वहीं, 394 करोड़ के सलेमपुर बाईपास का अब तक 32 फीसदी काम मुकम्मल हुआ है। राहत की खबर केवल तमकुहीराज-मझौली राष्ट्रीय राजमार्ग (लागत 192.27 करोड़) से आई, जिसका 24.745 किलोमीटर लंबा हिस्सा 82 प्रतिशत तक बनकर तैयार हो चुका है। चूंकि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन जुलाई 2026 है, इसलिए जिलाधिकारी ने शेष बचे कार्यों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तत्काल पूरा करने को कहा। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि बुनियादी ढांचा तैयार करने में खनन या भूमि अधिग्रहण से जुड़ी जो भी अड़चनें हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए, लेकिन काम बंद नहीं होना चाहिए।

स्टीमर बन्द होने से नौका संचालकों के समक्ष आया भूखमरी का संकट

जौनपुर।

गोमती नदी नौका (स्टीमर) संचालन समिति ने डीएम को सौंपा पत्रक

पर्यटकों के लिये शोभा बने गोमती नदी के नौका (स्टीमर) संचालन न होने से नौका स्वामियों के समक्ष भुखमरी की संकट आ गयी है। पिछले कई दिनों से रोजी–रोटी छीनने से परेशान लोगों ने सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर पत्रक सौंपा। गोमती नदी स्टीमर संचालन समिति गोपी घाट (शाही एवं सद्भावना पुल के बीच में) के बैनर तले पत्रक सौंपने वाले पीड़ितों का कहना है कि वह लोग गोमती नदी के किनारे रहने वाले मल्लाह बिरादरी के हैं जो अनादि काल से मछली का कारोबार करके परिवार का पेट पालते थे।

इधर यह व्यवसाय चौपट चल रही थी कि गोमती नदी के दोनों किनारों पर शासन–प्रशासन द्वारा बनवाये गये अछे घाट की वजह से लोगों का नदी के किनारे घूमने का प्रचलन शुरू हो गया। इसी को देखते हुये नाव को मोटिफाइट करके नौका (स्टीमर) संचालन का कारोबार किया जाने लगा जिससे परिवार का पेट पलने लगा। गत दिवस मध्य प्रदेश में हुये एक हादसे की वजह से यहां गोमती नदी में नौका (स्टीमर) संचालन बन्द कर दिया गया जिसके चलते लोगों के समक्ष रोटी के लाले पड़ गये हैं। पीड़ितों के अनुसार कोई सरकारी गाइड लाइन जारी करते हुये नौका (स्टीमर) संचालन को पुनः शुरू करवाया जाय, ताकि हम लोगों का रोजी–रोटी चल सके और हमारे परिवार का पेट पल सके। फिलहाल हम लोग लाइफ जैकेट के साथ नौका (स्टीमर) संचालन करते हैं। इसके अलावा यदि और कोई दिशा–निर्देश हो तो उसका भी पालन करने को तैयार हैं। जिलाधिकारी से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाने वालों में अनन्त निषाद, प्रदीप निषाद, अजीत निषाद, रंजीत निषाद, कुन्दन निषाद सहित तमाम नौका संचालक प्रमुख रहे। वहीं जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद जौनपुर के अधिशासी अधिकारी को मामले की जांच करके आख्या देने का आदेश दिया है।

जनता दर्शन में ऑन-स्पॉट जवाबदेही- कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोड़कर डीएम ने सीधे तहसीलदारों से पूछा– फाइल क्यों अटकी है?

देवरिया।

जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर तहसीलों तक जमीनी स्तर पर जनसुनवाई की स्थिति को धार देने और प्रशासनिक संवेदनशीलता को अमलीजामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित नियमित जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी का एक बिल्कुल अलग और सख्त प्रशासनिक रूप देखने को मिला। आम जनता की बुनियादी समस्याओं को सुनने के साथ ही जिलाधिकारी ने केवल मार्क करके फाइलों को आगे बढ़ाने की रवायत को तोड़ा। उन्होंने गंभीर और पेंडिंग मामलों में कलेक्ट्रेट से सीधे संबंधित उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व दूरभाष पर लाइव ले लिया और मौके पर ही लंबित प्रकरणों की वस्तुस्थिति जानकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी एक-एक फरियादी से व्यक्तिगत रूप से रूबरू हुए।

उन्होंने जमीन विवाद, आईजीआरएस पोर्टल की लंबित शिकायतों और राजस्व से जुड़े मामलों को बेहद संजीदगी से परखा। तकनीकी उपकरणों का सहारा लेते हुए मौके से ही ब्लॉक और तहसील स्तरीय अधिकारियों की वर्चुअल क्लास लेते हुए जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को त्वरित और पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना इस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने हिदायत दी कि जो भी अधिकारी जनसुनवाई के निर्धारित समय में दफ्तरों से नदारद पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी दफ्तरों में बैठकर केवल कागजी क्लोजर रिपोर्ट न लगाएं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि और धरातल की वास्तविकता के आधार पर मामलों का निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति सुदूर गांवों से किराया-भाड़ा लगाकर बड़ी उम्मीद के साथ जिला मुख्यालय पहुंचता है, ऐसे में अधिकारियों का यह नैतिक और विधिक दायित्व है कि वे उनकी पीड़ा को समझें। जिन मामलों में मौके पर जाकर जांच की आवश्यकता है, वहां राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें बिना किसी देरी के विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें।

इस उच्च स्तरीय डिजिटल और भौतिक जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्हें जिलाधिकारी ने हर एक आईजीआरएस शिकायत की क्लोज-मॉनिटरिंग करने का जिम्मा सौंपा है।

जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट कक्ष में सुनीं जनशिकायतें, मौके से ही फोन और रुकीन पर लिए गए एसडीएम व तहसीलदार

एसजी बोले- ऐसी घटना से अच्छा, हो जाए तलाक; सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- निष्पक्ष जांच जरूरी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा मामले का स्वत संज्ञान लेते सोमवार को इस पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने इस मामले को सनसनीखेज बनाने से बचने की भी सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा की मौत को अप्राकृतिक मृत्यु माना है। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में दो या तीन पहलू थे। पहला दूसरे पोस्टमार्टम से जुड़ा है, जो पूरा हो चुका है। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि कुछ कार्रवाइयों से हमें पीड़ा हुई है। हम अपने मीडिया मित्रों से अनुरोध करेंगे कि वे पीड़ित परिवार या दूसरे परिवार के बयान न लें। मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दें।

उम्मीद है, जांच में सच्चाई का पता लगाएंगे - सीजेआई

सीजेआई ने कहा कि सास पूर्व जिला न्यायाधीश हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह कहा जा रहा है कि न्यायपालिका निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने दे रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि पीड़ित और आरोपी जांच में सहयोग करेंगे। हमें अपनी सरकारी एजेंसियों और सीबीआई पर भी पूरा भरोसा है। जो भी जांच करेगा, वह निश्चित रूप से जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा।

गवाहों और आरोपियों के मीडिया में बयान देने पर रोक

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश और मृतका की सास गिरिबाला सिंह एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर त्विषा को बदनाम कर रही है। इससे जांच में बाधा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए संभावित गवाहों और आरोपियों के मीडिया को बयान देने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर ध्यान दिया है कि सीबीआई जांच के संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना करने से बेहतर है कि बेटी का तलाक हो जाए।

घटना की हो निष्पक्ष जांच - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि घटना की निष्पक्ष जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वह पीड़िता के परिवार के बयान रिकॉर्ड न करे और उनके दर्द को सनसनीखेज बनाने तक सीमित न करे। सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा के शव का तुरंत दूसरा पोस्टमार्टम कराने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सराहना की। आरोपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि पूर्व न्यायाधीश और त्विषा की सास गिरिबाला सिंह जांच के संबंध में मीडिया से कोई बयान नहीं देंगी।

आज से नौतपा, गर्मी-हीटवेव बढ़ेगी

नई दिल्ली । देश में आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है। इसका मतलब है कि अगले 9 दिन और ज्यादा गर्मी रहेगी। हीटवेव और तापमान भी बढ़ेगा। तापमान 45°C से ज्यादा बना रह सकता है। सोमवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 47.2°C रहा, जो सामान्य से 4.6°C ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में बांदा 46.8°C तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा। इसके अलावा प्रयागराज और उरई में 45.6°C, झांसी में 45.6°C, आगरा में 45.4°C और हमीरपुर में 45.2°C तापमान रिकॉर्ड हुआ। एमपी के दो शहरों, नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान 45.8°C दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत में 29 मई से मौसम बदल सकता है। बारिश की संभावना है।

ईंधन की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला

कहा- किश्तों में बढ़ रहे दाम ताकि चुपके से कटे जनता की जेब

नई दिल्ली । देश में आज चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इन बढ़ी हुई कीमतों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ईंधन के दाम एक साथ न बढ़ाकर टुकड़ों में बढ़ा रही है, ताकि आम जनता को इस जेबकटी का तुरंत अहसास न हो। उन्होंने पीएम को महंगाई मैन की संज्ञा देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यह जनता पर महंगाई का नया हमला है। उन्होंने कहा कि किश्तों में दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे है ताकि चुपके-चुपके नागरिकों की जेब पर डाका डाला जा सके। राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि वह पिछले कई महीनों से आने वाले आर्थिक संकट और तूफान को लेकर आगाह कर रहे थे। लेकिन, उस समय प्रधानमंत्री हमेशा की तरह चुनावी प्रचार में व्यस्त थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 8 रुपये की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है और आने वाले दिनों में यह इजाफा थमता हुआ नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार का केवल एक ही फॉर्मूला है। चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करना और चुनाव बीत जाने के बाद जनता की जेब पर सीधे वार करना।

ईरान शांति वार्ता में ट्रंप का नया पेंच: अब्राहम समझौते में शामिल होने की रखी शर्त; बोले- या तो महा-डील होगी या फिर भीषण जंग

वाशिंगटन/नई दिल्ली।

ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर चल रही बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया और कड़ा रुख अपनाकर दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा समझौते में प्रगति के संकेतों के ठीक बाद, ट्रंप ने एक नई शर्त थोप दी है। ट्रंप अब चाहते हैं कि ईरान सहित मिडिल ईस्ट के तमाम प्रमुख देश अब्राहम समझौते का हिस्सा बनें।

ट्रुथ सोशल पर ट्रंप की दो टूक चेतावनी

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट में स्पष्ट किया कि वाशिंगटन ने इस जटिल स्थिति को सुलझाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, -या तो यह सभी के लिए एक ग्रेट डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी— हम फिर से युद्ध के मैदान में होंगे और गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से कहीं बड़ी और भयावह होगी।

सऊदी अरब और कतर से की पहल की मांग

ट्रंप ने विशेष रूप से सऊदी अरब और कतर को पहले कदम उठाने के लिए कहा है।

उन्होंने अब्राहम समझौते की तारीफ करते हुए इसे शामिल देशों के लिए आर्थिक और सामाजिक बूम बताया है।

हालांकि, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे इस समझौते में तभी शामिल होंगे जब फिलिस्तीन के लिए दो-राष्ट्र समाधान का स्पष्ट रास्ता दिखेगा।

ईरान के लिए भी खुले हैं रास्ते

चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान को भी इस अब्राहम गठबंधन में शामिल होने का न्यौता दिया है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान उनके साथ समझौता करता है, तो उसे इस वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बनाना उनके लिए सम्मान की बात होगी।

भारत में रूबियो ने जताई थी उम्मीद, पर ईरान ने खींचे हाथ

दिलचस्प बात यह है कि यह नई मांग तब आई जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नई दिल्ली के दौरे के दौरान पत्रकारों से कहा था कि एक ठोस प्रस्ताव मेज पर है और जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने इन उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा कि हालांकि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि समझौता बिल्कुल करीब है।

हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया यूसीसी बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी

नई दिल्ली । असम सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है. इस बिल में कहा गया है कि यह असम में निवास करने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति (एसटी) पर लागू नहीं होगा. इसी लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यूसीसी एक जैसा नहीं है और यह आदिवासी समुदायों के खिलाफ है.

असम यूसीसी एक जैसा नहीं- ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, असम का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है. यह आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखता है. अनुच्छेद-29 के तहत हर समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ आदिवासियों की स्वायत्तता की ही रक्षा क्यों की जा रही है? यह एक ऐसा कानून थोपा जा रहा है जिसे कोई नहीं चाहता. संविधान सभा ने किसी अनिवार्य यूसीसी की कल्पना नहीं की थी.

जेंडर जस्टिस से कोसों दूर है कानून- ओवैसी

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, इस्लाम में कोई भी किसी वारिस को विरासत से वंचित नहीं कर सकता. कोई भी ऐसी वसीयत नहीं लिख सकता, जिससे अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ एक बेटे को दे दी जाए या बेटी को विरासत से वंचित कर दिया जाए, यह यूसीसी किसी को भी वसीयत लिखने और अपनी बेटियों को उनके उचित हिस्से से वंचित करने की अनुमति देता है. यह कानून जेंडर जस्टिस से कोसों दूर है.

असम यूसीसी बिल में क्या-क्या प्रावधान?

इस बिल में राज्य के सभी निवासियों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने वाले एक ही नागरिक कानूनी ढांचे का प्रस्ताव किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजातियों को उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों की रक्षा के लिए इससे बाहर रखा गया है. प्रस्तावित कानून का मकसद धर्म-आधारित कानूनों की जगह एक समान संहिता लाना है, जिसका लक्ष्य सभी समुदायों में लैंगिक न्याय, समानता और कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करना है. इस बिल के तहत एक-विवाह को अनिवार्य बना दिया गया है, जबकि शादी की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल तय की गई है. साथ ही यह कानून मौजूदा रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार शादियां करने की अनुमति देकर सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को भी बनाए रखता है.

मेकेदातु बांध विवाद पर सीएम विजय सख्त: अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक; कानूनी कार्रवाई तेज करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली । कावेरी नदी को लेकर लंबे समय से जारी विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। सरकारी बयान के मुताबिक, यह बैठक उस समय आयोजित की गई जब कर्नाटक में मेकेदातु परियोजना के लिए भूमि पूजन किए जाने की खबर सामने आई। तमिलनाडु सरकार पहले से ही इस परियोजना का विरोध करती रही है और उसका कहना है कि इससे राज्य के किसानों और सिंचाई व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। बैठक में कावेरी जल विवाद से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों और हालिया फैसलों की जानकारी दी। बताया गया कि शीर्ष अदालत पहले तमिलनाडु की पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुकी है, जिसमें यह कहा गया था कि इस मामले में तकनीकी और कानूनी निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के विशेषज्ञों के पास है। मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों से कहा कि अदालत के हालिया फैसलों को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा और किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी कदमों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। दरअसल, कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर मेकेदातु में एक बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाने की योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार का दावा है कि इस परियोजना से बेंगलुरु समेत कई इलाकों की पेयजल जरूरतें पूरी होंगी और बिजली उत्पादन में भी मदद मिलेगी। हालांकि, निचले तटीय राज्य तमिलनाडु का कहना है कि यदि यह परियोजना लागू होती है तो राज्य को मिलने वाले पानी की मात्रा प्रभावित हो सकती है। इससे कृषि क्षेत्र और लाखों किसानों पर असर पड़ने की आशंका है। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कानूनी रणनीति और आगे की कार्रवाई को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बांग्लादेश में भीषण सड़क हादसा

लोहे की छड़ों से लदा ट्रक पलटा, 15 लोगों की मौत; 10 घायल

ढाका । बांग्लादेश में सोमवार तड़के एक प्रमुख राजमार्ग पर लोहे की छड़ों से लदा एक ट्रक पलट जाने से 15 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ, जब लोग ईद-उल-अजहा की 10 दिवसीय छुट्टियों के लिए अपने गृहनगरों की ओर जा रहे थे। स्थानीय अग्निशमन केंद्र के प्रभारी अनवर रहमान ने संवाददाताओं को बताया कि यह दुर्घटना जमुना पुल के पूर्वी हिस्से में हुई, जो बांग्लादेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से को मध्य भाग से जोड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि घायलों को आसपास के इलाकों के लोगों की मदद से स्थानीय स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में ले जाया गया। स्थानीय पुलिस के अनुसार, ट्रक में लोहे की छड़ों के साथ-साथ कुछ यात्री भी सवार थे। चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण ट्रक तांगाइल के कालिहाटी उप-जिले में पलट गया। तांगाइल की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फौजिया हबीब खान ने बताया कि ट्रक चट्टोग्राम के दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर से उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र की ओर जा रहा था। यह संभव है कि ईद की भीड़ के कारण पीड़ित रास्ते में अलग-अलग जगहों से ट्रक में सवार हुए हों। बांग्लादेश में सोमवार से ईद-उल-अजहा की 10 दिवसीय छुट्टियां शुरू हुई हैं। लोग त्योहार के लिए अपने घरों की ओर जा रहे हैं, जिससे बसें, ट्रेनें और नौकाएं खचाखच भरी हुई हैं। गरीब लोग अक्सर कम लागत के कारण या नियमित यात्री वाहनों में टिकट न मिलने पर ट्रकों से यात्रा करते हैं।

अमृतसर में कपिल शर्मा के घर पर फायरिंग का दावा : 2 राउंड फायरिंग की, पुलिस का इनकार

अमृतसर। कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा के अमृतसर स्थित घर के बाहर सोमवार को फायरिंग होने की खबर आई। कपिल के परिवार से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि हमलावर बाइक पर आए और 2 राउंड फायरिंग करके भाग गए। अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। सीपी कमलजीत सिंह औलख ने कहा- गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है। अमृतसर के पॉश इलाके हॉली सिटी में कपिल शर्मा का घर है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए। घर और आसपास के वीआईपी घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया। इस घर में कपिल के बहन और जीजा रहते हैं, जबकि कपिल शर्मा फिलहाल परिवार के साथ मुंबई में हैं। इससे पहले उनके कनाडा में स्थित कैफे पर 3 बार फायरिंग हुई थी। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि फायरिंग की घटना को लेकर कुछ गैर-जिम्मेदार लोग अफवाहें फैला रहे हैं। सभी से अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सोर्स से जारी सही जानकारी पर ही भरोसा करें।

पेट्रोल-डीजल संकट की खबरों पर सरकार का बड़ा बयान, कहा- देश में तेल की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर न दें ध्यान

नेशनल डेस्क । देश के कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों के बाद पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भारी भीड़ लग गई है। ऐसे हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्थिति साफ की है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है। वर्तमान में देश में कोई पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ जिलों में यह समस्या देखी गई है। देश में ईंधन की आपूर्ति को ठीक ढंग बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार तेल एजेंसियों के संपर्क में हैं।

मंत्रालय ने बताए डिमांड के मुख्य कारण

पेट्रोलियम सचिव ने पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ने के मुख्य कारणों को स्पष्ट करते हुए बताया कि कुछ इलाकों में खेतीबाड़ी के कामों के लिए डीजल की मांग में अचानक तेजी आई है। इसकेअलावा देश में ईंधन की कमी की अफवाहों के बीच लोग ईंधन अधिक मात्रा में खरीद रहे हैं। कुछ निजी तेल सप्लायर्स की मांग भी अब सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों और उनके पेट्रोल पंपों पर शिफ्ट हो गई है, जिससे सरकारी पंपों पर दबाव बढ़ गया है।

पल-पल की नजर रख रहा है मंत्रालय

पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा देश के प्रत्येक रिटेल पेट्रोल पंप की सप्लाई चेन की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके पीछे सरकार का मकसद है कि जहां पर भी स्टॉक कम है वहां पर उस कमी को पूरा किया जाए, ताकि लोगों को कोई भी असुविधा न हो।

अफवाहों के बीच पंपों पर लगी लंबी कतारें

देश में ईंधन की अफवाहों के बीच उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही है। गाड़ियों की टंकी फुल करवाने के अलावा लोग बोतलों, कंटेनरों में पेट्रोल- डीजल का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं।

अचानक बढ़ी इस भारी मांग के कारण कुछ पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से तेल खत्म होने की स्थिति बन गई, जिससे स्थानीय ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग करके ईंधन का स्टॉक जमा न करें।

देश के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी- दिल्ली में बिजली की मांग बढ़ी

हैदराबाद।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तेलंगाना के कई जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि सोमवार और मंगलवार को मुलुगु, खम्मम और आसपास के जिलों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। आईएमडी के मौसम केंद्र ने अगले सात दिनों के लिए जारी चेतावनी में कहा कि सोमवार को पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम और खम्मम जिलों के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। विभाग ने यह भी कहा कि आदिलाबाद, निजामाबाद, हैदराबाद और अन्य जिलों में रात के समय भी गर्मी बनी रह सकती है। विकाराबाद, संगारेड्डी, मेडक और अन्य जिलों में गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मंगलवार को भी जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम और खम्मम जिलों में लू का असर जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि 27 और 28 मई को भी कुछ इलाकों में लू चल सकती है। राज्य के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने 23 मई को कहा था कि इस गर्मी में राज्य में लू के कारण 16 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की सहायता देगी।

पश्चिम बंगाल- भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना

पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को आज राहत मिल सकती है। आईएमडी ने गरज के साथ बारिश और आंधी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा कि गुरुवार से राज्य के अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आ सकती है। पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान जैसे जिलों में तेज गर्मी का असर देखा गया और तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। मौसम कार्यालय ने कहा कि अगले दो दिनों तक गर्मी बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद बारिश और आंधी के कारण तापमान में कमी आ सकती है। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहा, जिससे लोगों को परेशानी हुई। वहीं,

उत्तर बंगाल के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। रायगंज में सबसे ज्यादा 74.8 मिमी बारिश हुई। कोलकाता में सोमवार को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग ने शाम में कुछ इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है।

राजस्थान-श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान

राजस्थान में भी भीषण गर्मी जारी है। पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के कई हिस्सों में लू, गर्म रातें और धूल भरी आंधियां देखने को मिलीं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि इस सप्ताह राज्य के कुछ इलाकों में भीषण लू चल सकती है और अगले दो-तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में 26 और 27 मई को तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ जगहों पर गंभीर लू की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि 28 और 29 मई से पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आ सकती है। विभाग ने कहा कि जून के पहले सप्ताह में भी आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

दिल्ली- मई महीने में अब तक की सबसे ज्यादा बिजली मांग दर्ज

भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में सोमवार को मई महीने में अब तक की सबसे ज्यादा बिजली मांग दर्ज की गई। राज्य विद्युत भार प्रेषण केंद्र के अनुसार, दोपहर 3:35 बजे बिजली की मांग 8,439 मेगावाट तक पहुंच गई। पिछले छह दिनों में यह चौथी बार है, जब मांग 8,000 मेगावाट के पार गई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल मई में बिजली की मांग 8,000 मेगावाट से कम रही थी। दिल्ली में गर्मी बढ़ने के कारण इस महीने बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। सोमवार को दिल्ली में मई की पिछले लगभग 14 वर्षों की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.7 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग के अनुसार मई में इससे ज्यादा न्यूनतम तापमान आखिरी बार 26 मई 2012 को दर्ज किया गया था। सोमवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बिजली कंपनियों ने कहा कि उन्होंने बढ़ती मांग के बावजूद बिना किसी कटौती के बिजली आपूर्ति बनाए रखी।